

सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएँ एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

*श्रीमती मनीषा शर्मा, विभागाध्यक्ष, राजनीति विभाग

**डॉ. गिरिजा निगम, प्राचार्य,

*आदर्श इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड साईंस, धामनोद

**शासकीय महाविद्यालय, तराना,

मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

एक सफल सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि जनता की समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान खोजना। इस कार्य को करने में सरकार की क्या भूमिका है और वह किस माध्यम से योजनाओं का निर्माण करती है एवं उनके क्रियान्वयन में कहां तक सफल हुई है एवं जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश में शासन द्वारा संचालित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावना

जमीनी समस्याओं के निदान के लिये राजनीतिक कुशलता तथा समय की आवश्यकता होती है। योजना के क्रियान्वयन के लक्ष्य आसानी से निर्धारित हो जाते हैं परन्तु परिणाम देरी से आते हैं। यही कारण है कि भाजपा की निर्वाचन 2004 की घोषित योजनाओं के अधूरे परिणाम निर्वाचन 2008 के पश्चात् देखे गए, जिसके बेहतर प्रभाव रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में है लेकिन अध्ययन की इकाई के रूप में विशेषकर खरगोन जिले को लिया गया है। जिसके अंतर्गत जिले में 9 तहसीलें तथा विकासखण्ड हैं, जिसके अंतर्गत खरगोन, बड़वाह, भगवानपुरा, सेगाँव, भीकन गाँव, झीरन्या, महेश्वर, बड़वाह, कसरावद, गोगांवा सम्मिलित हैं। 25 नवम्बर 1956 में नवीन मध्यप्रदेश का निर्माण हुआ। नव निमाड़ प्रदेश को दो जिला प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया।

पश्चिम में खरगोन जिला अर्थात् पश्चिम निमाड़ तथा पूर्व में खण्डवा जिला अर्थात् पूर्वी निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं।

खरगोन जिले का भौगोलिक महत्त्व

खरगोन जिला 21.22 से 22.23 उत्तरी अक्षांश 75.19 से 76.14 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा जिले के ऊपरी बिन्दु से लगभग 101 कि.मी. से दूर गुजरती है। प्राकृतिक रूप से यह जिला नर्मदा घाटी का मध्यवर्ती भाग है, जिसकी उत्तरी विन्ध्य कगार तथा दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। जिले का कुल क्षेत्रफल 13485 वर्ग कि.मी. है। उत्तर में धार एवं इंदौर तथा दक्षिण में बड़वानी जिला तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा है। जिला मुख्यालय खरगोन की समुद्र तल से ऊँचाई 259 मीटर है। सबसे अधिक 416 मी. की ऊँचाई सेंधवा तहसील है और सबसे कम बड़वाह 102 मीटर है।

शोध का उद्देश्य - सामान्यतः अनुसंधान हेतु निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्ययनकर्ता को

कुछ शोध प्रश्नों अथवा परीक्षणार्थ परिकल्पनायें निर्मित करनी होती हैं। अध्ययन के अन्तिम सोपान में इन परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण करके निष्कर्ष उद्घाटित (स्थापित) किये जाते हैं, जिसे सिद्धान्तीकरण कहते हैं। अध्ययनकर्ता ने भी कतिपय परिकल्पनाएँ निर्मित की हैं। अनुसंधान कार्य हेतु यह परमावश्यक होता है कि सर्वप्रथम 'परिकल्पनाएँ' शब्द की अवधारणा स्पष्ट कर ली जाए। सामान्यतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना (परि+कल्पना) दो शब्दों का योग है, जिनके अर्थ क्रमशः 'चारों ओर' तथा 'विचार या चिन्तन करना' है अर्थात् अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में एक सामान्य अनुमान के आधार पर विचार करना। इस प्रकार एक शोधकर्ता अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के पूर्व ही अध्ययन की समस्या के विभिन्न पक्षों तथा उद्देश्यों से सम्बन्धित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है, जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा निर्धारित करना होता है ताकि अध्ययनकर्ता इधर-उधर निरर्थक न भटक कर सुनिश्चित आधार पर सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करता है।

उद्देश्य

इस दृष्टिकोण से इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. मध्यप्रदेश में वर्तमान सरकार का अध्ययन करना।
2. मध्यप्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त योजना की जानकारी क्रियान्वयन प्रभाव एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारी एकत्रित करना।
3. चुनावी घोषणा पत्रों का सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएं

किसी भी शोध को केन्द्रित करने के लिये परिकल्पनाओं का सहारा लेना आवश्यक है, जिससे शोध को दिशा निर्देश दिया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निर्देशित दिशा की ओर ले जाने हेतु कुछ उपकल्पनाओं (पूर्वानुमानित निष्कर्षों) का निर्माण किया गया है और इन्हीं उपकल्पनाओं को (निष्कर्ष को) उत्तरदाताओं की सहायता से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणीकृत करने की चेष्टा की गयी है।

म.प्र. में वर्तमान सरकार द्वारा प्रदत्त योजना -

विकास की अवधारणा को एक स्पष्ट रूप देने का एक तरीका राष्ट्र की प्रगति को इसके सबसे गरीब हिस्से की प्रगति के संदर्भ में मापना है, ताकि जनसंख्या के निचले हिस्से की प्रगति हो सके तथा निचले हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सके और इसकी आय की वृद्धि दर को आंका जा सके निर्धनतम हिस्से से जुड़े इन उपायों के संदर्भ में हमारी आर्थिक सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। यह तरीका आकर्षक है क्योंकि इसमें विकास को उस तरह नजर अंदाज नहीं किया जाता जैसे कुछ पुराने अपरांपरागत मापदंड तय करते रहे हैं। इसमें जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों की आय में हुई वृद्धि को देखा जाता है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो लोग निचले हिस्से से बाहर हैं, उनकी उपेक्षा न हो। पूरी संभावना है कि वे लोग निचले हिस्से में शामिल हो जाएंगे और इस तरह स्वतः ही नीतियों को सीधा लक्ष्य के रूप में तय किया गया है। नीतिगत परिचर्चा में इस बात से प्रेरित किया है जो आगे निष्कर्षों तक ले जाता है। भारत में उच्च विकास हासिल करने का प्रयास किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये काम

करना चाहिए कि सबसे कमजोर वर्ग इस सम विकास योजना से लाभान्वित हो सके।

मध्यप्रदेश की आबादी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है। इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कार्य कर रहा है। राज्य में लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कई संस्थाएँ एवं योजनाएँ संचालित हैं। राज्य शासन का ध्यान राज्य में तेजी से बढ़ती जनसंख्या की तरफ भी है, जो विकास में एक बाधक तत्व है। अतः अपनी स्वास्थ्य नीति में इसे भी शामिल किया गया है।

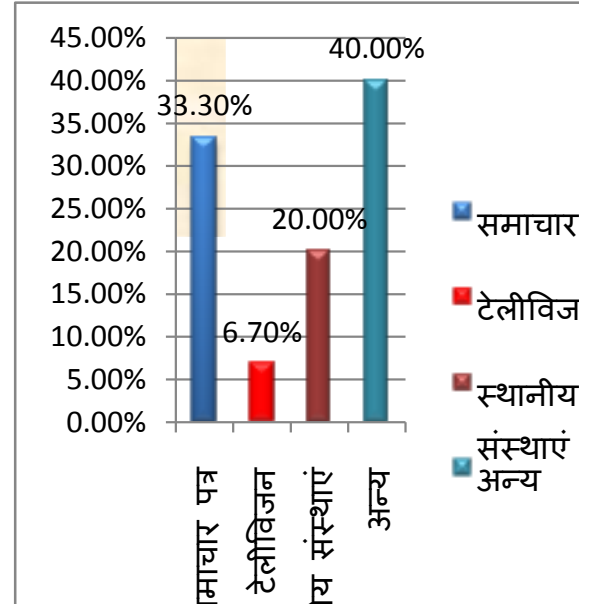
भाषण की योजनाएं एवं ज्ञान के संबंध में

सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएं एवं क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन -

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त लोकप्रिय योजनाएं एवं लाभ के सम्बन्ध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में निवासरत उत्तरदाताओं में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, विशिष्टजन, शिक्षक एवं आमजन कुल 300 उत्तरदाताओं से भाषण की योजना के संबंध में अभिमत जानने का प्रयास किया गया। जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है -

शासन की योजनाएँ एवं ज्ञान के संबंध में

| क्र. | अभिमत | आवृत्ति | प्रतिशत |
|------|------------------|---------|---------|
| 01 | समाचार पत्र | 100 | 33.3% |
| 02 | टेलिविजन | 20 | 06.7% |
| 03 | स्थानीय संस्थाएं | 60 | 20.0% |
| 04 | अन्य | 120 | 40.0% |
| | योग | 300 | 100% |



सारणी में 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि भाषण की योजना एवं ज्ञान के संबंध में उन्हें अन्य स्रोतों जैसे - पास-पड़ोस, सामुदायिक संगठन, स्थानीय नेताओं से जानकारी प्राप्त होती है। 33.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि समाचार-पत्रों के माध्यम से भाषण की योजना की जानकारी प्राप्त होती है। क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी स्थानीय संस्था एवं टेलिविजन के माध्यम से प्राप्त होती है।

अतः हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि अन्य स्रोतों का प्रभाव उत्तरदाता पर अधिक पड़ा है।

निष्कर्ष

दस सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मध्यप्रदेश से 'बीमारू राज्य' का शर्मनाक तमगा हट चुका है। सड़कें बेहतर हैं, बिजली की स्थिति में काफी हद तक सुधार आया है। प्रदेश में स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है। प्रदेश में विकास का नया विजन आया है। कई ऐसी परियोजनाएँ पूरी की हैं जो उन्हें प्रदेश को



एक अलग स्थान प्रदान कर रही हैं। प्रदेश में और भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिनसे प्रदेश की तस्वीर और बदलेगी। बड़े-बड़े समूह शिक्षा में निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 31
2. मध्यप्रदेश "आज और कल" प्रकाशक रामभुवन सिंह कुशवाह, अरूणा कुशवाह, प्रियंका आफसेट 25 प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल पृष्ठ सं. 53
3. अवस्थी मध्यप्रदेश प्रदेश प्रशासन, हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ सं. 26
4. पथ नया अवसर नया, प्रकाशक म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल पृष्ठ सं. 77
5. "सबका साथ सबका विकास" प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क, भोपाल पृष्ठ सं. 83
6. मध्यप्रदेश संदेश, अंक 9 सितम्बर 2012, पृष्ठ सं. 21
7. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टेगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 58
8. जिला गजेटियर विभाग भोपाल, पृष्ठ सं. 124
9. जैन पी.सी., संगठनात्मक व्यवहार, सरस्वती पब्लिकेशंस, जयपुर 1992 पृष्ठ सं. 58
10. कपूर अनूपचन्द्र, संसार की प्रमुख शासन प्रणालियाँ, एस. चन्द एण्ड कं., नई दिल्ली, 1966 पृष्ठ सं. 207
11. कोठारी रजनी, कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, ओरिएण्ट लाँगमेन, दिल्ली, 1970 पृष्ठ सं. 69
12. कोठारी रजनी, पालिटिक्स इन इण्डिया, ओरिएण्ट लाँगमेन, दिल्ली, 1972 पृष्ठ सं. 72
13. लिमये मधु, कांग्रेस - इट्स स्ट्रैथ एण्ड वीकनेस, हिन्दू जुलाई 16, 1992 पृष्ठ सं. 23
14. माहेश्वरी महेश कुमार, मध्यप्रदेश राजनीति के विविध आयाम, प्रिंटवेल प्रकाशन, जयपुर, 1996 पृष्ठ सं. 64
15. नान्देकर बी.जी., लोकल गवर्नमेंट - इट्स रोल इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कान्सेप्ट, नई दिल्ली, 1970 पृष्ठ सं. 117

16. पाण्डेय सुरेन्द्र, आम चुनाव में जाति एवं सम्प्रदाय, एस.के. पब्लिशिंग कम्पनी, राँची, 2004 पृष्ठ सं. 59
17. पाण्डेय रामकृष्ण, भारतीय प्रजातांत्रिक पद्धति में नागरिक असंतोष, पब्लिकेशंस स्कीम, जयपुर 1999 पृष्ठ सं. 37
18. राठौर मीना, भारत में राजनैतिक दल, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 पृष्ठ सं. 57
19. शर्मा आर.पी., द फ्यूचर आफ डेमोक्रेसी इन इण्डिया, द इण्डियन पब्लिकेशंस, 1963 पृष्ठ सं. 86,87
20. शर्मा राजेन्द्र कुमार, राजनैतिक समाजशास्त्र, अटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 1996 पृष्ठ सं. 29
21. शर्मा साधना, स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 1995 पृष्ठ सं. 93
22. शर्मा हरीशचन्द्र, भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1999 पृष्ठ सं. 106
23. त्रिवेदी आर.एन. एवं राय एम.पी., भारतीय सरकार एवं राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1999 पृष्ठ सं. 213
24. वाजपेयी अन्तिमा, भारतीय निर्वाचन पद्धति, नार्दर्न बुक डिपो (सेंटर), दिल्ली, 1992 पृष्ठ सं. 47
25. वाजपेयी अशोक, पंचायती राज एवं रूरल डेवलपमेंट, 1998 पृष्ठ सं. 61
26. गोयल ओ.पी., काॅस्ट एण्ड वोटिंग बिहेवियर 1978 पृष्ठ सं. 85